

व्यय दक्षता और सरकारी परियोजना प्राधिकरण, जिसे आम बोलचाल की भाषा में EXPro के नाम से जाना जाता है, एक सरकारी इकाई है जिसे कैबिनेट के निर्देशों के आधार पर स्थापित किया गया था। इस निकाय के गठन का निर्णय 23 फरवरी, 2021 को लिया गया था, जो एएच (एन्रो हेगिरा) इस्लामी कैलेंडर में रजब 11, 1442 के बराबर है।

यह प्रतिष्ठान संकल्प संख्या 389 के तहत अधिनियमित किया गया था। इस संकल्प के अनुसार, सार्वजनिक संस्थाओं में परियोजना प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे 'परियोजनाएं' भी कहा जाता है, को व्यय दक्षता उपलब्धि केंद्र में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। संकल्प में आगे निर्दिष्ट किया गया है कि इस केंद्र को फिर EXPro में पुनर्गठित किया जाएगा, इस प्रकार सरकारी ढांचे के भीतर व्यय और परियोजना दक्षता प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

इस परिवर्तन के पीछे का उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करना और सरकारी परियोजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना था। राष्ट्रीय कार्यक्रम को पुनर्निर्मित केंद्र में आत्मसात करने के माध्यम से, जिम्मेदारियों का दायरा व्यापक हो गया, जिससे अंततः वर्तमान व्यय दक्षता और सरकारी परियोजना प्राधिकरण का विकास हुआ।

व्यय दक्षता और सरकारी परियोजना प्राधिकरण (EXPro) की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- व्यय दक्षता हासिल करना: EXPro का एक मूल उद्देश्य सभी सरकारी एजेंसियों में वित्तीय दक्षता को बढ़ावा देना है। इसमें अनावश्यक व्यय को कम करने और इष्टतम संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए धन की सावधानीपूर्वक योजना और प्रबंधन शामिल है।
- सरकारी परियोजनाओं और संचालन की गुणवत्ता में सुधार: EXPro का लक्ष्य सरकारी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करना है। यह भी शामिल है:
 - 1) राज्य-वित्त पोषित परियोजनाएँ: यह सुनिश्चित करना कि ये परियोजनाएँ संचालन के उच्च मानकों का पालन करें, हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करें।
 - 2) संपत्तियाँ और सुविधाएँ: सभी सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों और सुविधाओं के प्रबंधन और उपयोगिता को बढ़ाना।
 - 3) बुनियादी ढाँचा योजना: यह सुनिश्चित करना कि बुनियादी ढाँचा विकास योजनाएँ समकालीन मानकों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
 - 4) कार्यक्रम और पहल: यह गारंटी देना कि सभी सरकारी कार्यक्रम और पहल जनता के लिए प्रभावी, कुशल और लाभकारी हैं।
 - 5) परिचालन प्रक्रियाएँ: सरकारी सेवाओं की तरलता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन प्रक्रियाओं का अनुकूलन।
- लगातार निगरानी और अनुवर्ती: EXPro पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्धारित इन कार्यों, कार्यक्रमों और पहलों की लगातार निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। इसके माध्यम से प्रगति को ट्रैक करना और प्राधिकरण के उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करना संभव हो जाता है। यह सभी संस्थाओं को अधिक कुशल और बेहतर सरकारी संचालन की दिशा में एक ही रास्ते पर रखता है।

इन लक्ष्यों को पूरा करके, EXPro सरकारी मशीनरी के कामकाज में सुधार करने, इसे अधिक संगठित, कुशल और जनता के लिए फायदेमंद बनाने का काम करता है।

व्यय दक्षता और सरकारी परियोजना प्राधिकरण (EXPro) के पास इसके मिशन से संबंधित कई आवश्यक कार्य और जिम्मेदारियाँ हैं:

- नीतियाँ, रणनीतियाँ, योजनाएँ, कार्यक्रम और मानक विकसित करना: EXPro को महत्वपूर्ण नीतियों, रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और मानकों को तैयार करने का काम सौंपा गया है जो प्राधिकरण की दक्षताओं के अनुरूप हैं। यह संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय में किया जाता है, और प्राधिकरण द्वारा इनके कार्यान्वयन का बारीकी से पालन किया जाता है।
- विधान और विनियमों का प्रस्ताव करना: एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य नए कानून और विनियमों का प्रस्ताव करना है जो प्राधिकरण की शक्तियों के लिए प्रासंगिक हैं। इसमें बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप या बेहतर दक्षता के लिए मौजूदा में संशोधन का सुझाव देना भी शामिल है।
- व्यय विवरण का अध्ययन: EXPro सरकारी एजेंसियों में परिचालन, पूंजीगत व्यय प्रथाओं के विस्तृत अध्ययन और व्यय दक्षता बढ़ाने के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार है।
- सहयोगात्मक टीमों का गठन: एक्सप्रो संयुक्त कार्य टीमों के गठन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। इस पहल का उद्देश्य व्यय दक्षता को बढ़ावा देना और परियोजनाओं, पहलों और परिचालन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- संकेतक और मानक स्थापित करना: एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण संकेतक, मानक, उपकरण, कार्यप्रणाली और तरीकों की स्थापना है जो प्राधिकरण की दक्षताओं के साथ संरेखित होते हैं। इससे इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी मदद मिलती है और क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की अनुमति मिलती है।
- रिपोर्ट तैयार करना: नियमित अंतराल पर, एक्सप्रो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सिफारिशों, कार्यप्रणाली, तंत्र और मानकों के प्रति सरकारी एजेंसियों की प्रतिबद्धता को मापने के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। फिर इन व्यावहारिक रिपोर्टों को समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। यहां उद्देश्य सभी सरकारी एजेंसियों में सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों का लगातार पालन सुनिश्चित करना है।

EXPro ने शैक्षिक और परिचालन दक्षता का आकलन करने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रदर्शन संकेतकों की एक श्रृंखला पेश की है। ये संकेतक व्यय दक्षता के लिए समर्पित टीमों के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के नेताओं की सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। संकेतक विशिष्ट लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति पर नज़र रखने और उसका आकलन करने में सहायक होते हैं।

इन प्रदर्शन संकेतकों के महत्व को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है:

- जागरूकता बढ़ाना: ये प्रदर्शन संकेतक शैक्षणिक संस्थान के वास्तविक समय के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अपेक्षित और इष्टतम स्तरों के खिलाफ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं।
- पारदर्शिता बढ़ाना: संस्थान के अंदर और बाहर इन संकेतकों का माप और आवधिक प्रकाशन पारदर्शिता में काफी वृद्धि करता है। यह दृष्टिकोण हितधारकों को संस्थान के प्रदर्शन और प्रगति के बारे में सूचित रखता है।
- प्रदर्शन का निदान: प्रदर्शन संकेतक शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन में संभावित अंतराल की पहचान करने में मदद करते हैं। किसी आदर्श या इष्टतम स्थिति के विरुद्ध वर्तमान स्थिति की तुलना करके, किसी भी असमानता या सुधार के क्षेत्रों को आसानी से पहचाना जा सकता है।

- प्रदर्शन प्रबंधन: ये संकेतक संस्थान के भीतर एजेंसियों और क्षेत्रों के लिए प्रेरणा के रूप में भी कार्य करते हैं। स्पष्ट और मापने योग्य संकेतक होने से, ये टीमों रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने के लिए सशक्त होती हैं।
- लक्ष्यों और लक्ष्यों की उपलब्धि को मापना: प्रदर्शन संकेतकों की एक अभिन्न भूमिका निर्धारित लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को मापना है। विवेकपूर्ण ढंग से डिज़ाइन किए गए मापदंडों के माध्यम से, संकेतक निष्पक्ष रूप से प्रगति और उपलब्धियों को माप सकते हैं।

संक्षेप में, EXPro द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन संकेतक व्यय दक्षता की दिशा में किसी संस्थान के प्रदर्शन को प्रबंधित करने और ट्रैक करने में अमूल्य महत्व रखते हैं। वे उच्च शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही, पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।

EXPro द्वारा मानकीकृत संकेतकों का कार्यान्वयन शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान पैमाना प्रदान करता है। ये संकेतक अन्य संस्थानों में देखी गई सर्वोत्तम स्थानीय प्रथाओं के लाभों को प्रकाश में लाते हैं, जिससे सभी संस्थानों में साझा सीखने और विकास के माहौल को बढ़ावा मिलता है।

प्रदर्शन संकेतकों का महत्व:

- सुधार के अवसरों की पहचान करना: ये प्रदर्शन संकेतक व्यय दक्षता को बढ़ावा देने के संभावित अवसरों की दिशा में एक रोडमैप के रूप में कार्य करते हैं। इन संकेतकों के विरुद्ध प्रदर्शन की तुलना करके, उच्च शिक्षा संस्थान उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां परिवर्तन व्यय दक्षता को बढ़ा सकते हैं।
- प्रदर्शन माप: शैक्षिक और प्रशिक्षण दक्षता को मापने के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन संकेतक किसी विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के मात्रात्मक माप के रूप में कार्य करते हैं। वे संस्थानों को उनकी परिचालन दक्षता का आकलन करने में मदद करते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करते हैं जहां सुधार शैक्षिक परिणामों को बढ़ा सकता है।

संक्षेप में, सावधानीपूर्वक प्रस्तावित प्रदर्शन संकेतकों के साथ संयुक्त संकेतकों का मानकीकरण एक शक्तिशाली उपकरण बनता है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी प्रगति का आकलन करने, सुधार के अवसरों की पहचान करने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। यह, बदले में, व्यय दक्षता में समग्र सुधार प्राप्त करने में सहायता करता है।

नीचे उल्लिखित प्रदर्शन संकेतक और उनकी गणना विधियां/तंत्र/सूत्र हैं जो यह जांचने में सहायता के लिए स्थापित किए गए हैं कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर का अधिकतम लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली टीमों की मदद करना है, साथ ही इन संस्थानों के प्रभारी लोगों का मार्गदर्शन करना है। वे हमारे लक्ष्यों और योजनाओं को पूरा करने में कितनी प्रगति हो रही है, इस पर नज़र रखने और मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. मान्यता प्राप्त कार्यक्रम (राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय): स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या ÷ शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की कुल संख्या
2. स्वतंत्र मानकीकृत परीक्षणों के परिणाम: स्वतंत्र मानकीकृत परीक्षणों पर औसत छात्र परिणाम (माप केंद्र के माध्यम से उच्च शिक्षा में सीखने के परिणामों का आकलन)
3. छात्र प्रतिधारण: पिछले वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से अगले वर्ष में स्थानांतरित होने वाले छात्रों की संख्या ÷ पिछले वर्ष में प्रवेश की कुल संख्या।

4. समय पर स्नातक: न्यूनतम नियमित स्नातक अवधि के भीतर कार्यक्रम से स्नातक होने वाले स्नातक छात्रों की संख्या ÷ एक ही वर्ष में स्नातक स्नातकों की कुल संख्या।
5. रोजगार (6 महीने): (पिछले वर्ष में स्नातक स्नातकों की संख्या जिन्होंने स्नातक होने के (6) महीनों के भीतर नौकरी प्राप्त की + पिछले वर्ष में स्नातक स्नातकों की संख्या जिन्हें राज्य के अंदर या बाहर स्नातक कार्यक्रमों में स्वीकार किया गया था और प्राप्त नहीं किया स्नातक होने के (6) महीने के भीतर नौकरी) ÷ वर्ष में स्नातक स्नातकों की कुल संख्या
6. उद्यमशीलता गतिविधि: पिछले 24 महीनों में पूर्णकालिक व्यवसाय स्थापित करने वाले स्नातकों की संख्या ÷ पिछले 24 महीनों में स्नातकों की कुल संख्या।
7. कर्मचारी-संकाय अनुपात: विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या (संकाय को छोड़कर) ÷ संकाय और प्राधिकारी पदों पर बैठे लोगों की कुल संख्या
8. संकाय द्वारा सौंपे गए प्रशासनिक कार्यों का प्रतिशत: शैक्षणिक संस्थान के भीतर प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे गए संकाय सदस्यों की संख्या ÷ शोध या प्रशासन के लिए छुट्टी पर गए संकाय सदस्यों को छोड़कर, नौकरी पर मौजूद संकाय सदस्यों की कुल संख्या।
9. छात्र-संकाय अनुपात: पूर्णकालिक छात्रों की कुल संख्या ÷ अनुसंधान या प्रशासन के लिए छुट्टी पर गए लोगों को छोड़कर संकाय सदस्यों की कुल संख्या।
10. संकाय उपयोग दर: सभी संकाय सदस्यों के लिए कुल वास्तविक शिक्षण भार (शैक्षणिक समय) ÷ शिक्षण भार के लिए अनुमोदित नियमों के अनुसार काम पर मौजूद सभी संकाय सदस्यों के लिए कुल शिक्षण क्षमता।
11. अनुसूची अधिभोग दर: सभी विभागों में पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या ÷ सीटों की संख्या के संदर्भ में सभी विभागों की कुल अधिकतम क्षमता।
12. कक्षा अधिभोग दर: निरंतर छात्रों की कुल संख्या ÷ कक्षाओं की अधिकतम क्षमता।
13. *अधिकतम कक्षा क्षमता = ((सीटों के संदर्भ में कुल कक्षा क्षमता (दोहराव के बिना) × (प्रति सप्ताह उपलब्ध घंटों की संख्या)) ÷ (छात्र के लिए पंजीकृत घंटों की औसत संख्या))।
14. दूरस्थ शिक्षा: दूरस्थ शिक्षा के लिए पंजीकृत घंटों की संख्या ÷ संस्था स्तर पर पंजीकृत घंटों की कुल संख्या।
15. पाठ्यक्रम विलोपन: सेमेस्टर के दौरान पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों की संख्या ÷ सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या।
16. श्रम बाजार के लिए आवश्यक विशेषज्ञता में स्नातक: श्रम बाजार के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के लिए स्नातक कार्यक्रम स्नातकों की संख्या ÷ स्नातक कार्यक्रम स्नातकों की कुल संख्या।
17. शीर्ष (50) शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति: शीर्ष (50) शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या (पिछले पांच वर्षों के दौरान क्यूएस-शंघाई-टाइम्स विश्व रैंकिंग के अनुसार) ÷ पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या।
18. समय पर विद्वानों का स्नातक: छात्रवृत्ति पर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या, जो न्यूनतम नियमित छात्रवृत्ति अवधि से अधिक हो गए हैं ÷ छात्रवृत्ति पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या।
19. रैंक वाली वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध: सहकर्मि-समीक्षित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या ÷ वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या।
20. स्व-निर्मित राजस्व: सऊदी रियाल में कुल स्व-उत्पन्न राजस्व ÷ सऊदी रियाल में शैक्षणिक संस्थान का कुल वार्षिक बजट।

21. छात्र लागत दर: शैक्षणिक संस्थान का कुल व्यय (पूँजीगत परियोजनाओं पर व्यय को छोड़कर) ÷ शैक्षणिक संस्थान में छात्रों की कुल संख्या।
22. संचालन और रखरखाव लागत दर: पिछले वर्ष के संचालन और रखरखाव अनुबंधों पर कुल व्यय (रियाल) ÷ संचालन और रखरखाव द्वारा शैक्षणिक संस्थान का कवर किया गया क्षेत्र
23. सफ़ाई लागत दर: सफ़ाई सेवाओं द्वारा कवर किए गए शैक्षणिक संस्थान का क्षेत्र (वर्ग मीटर) ÷ अनुबंध में श्रमिकों की कुल संख्या
24. जल उपभोग दर: शैक्षणिक संस्थान की कुल वार्षिक जल खपत (घन मीटर) ÷ उसी वर्ष के लिए शैक्षणिक संस्थान के लाभार्थियों (छात्रों और कर्मचारियों) की कुल संख्या।
25. बिजली की खपत दर: शैक्षणिक संस्थान की कुल वार्षिक बिजली खपत (किलोवाट-घंटे) ÷ उसी वर्ष के लिए शैक्षणिक संस्थान के लाभार्थियों (छात्रों और कर्मचारियों) की कुल संख्या।
26. प्रति वाहन ईंधन खपत: कुल ईंधन खपत (लीटर) सेवा में सक्रिय वाहनों की कुल संख्या।
27. प्रति कर्मचारी वाहन दर: शैक्षणिक संस्थान से संबंधित वाहनों की कुल संख्या ÷ उन कर्मचारियों की संख्या जिनके काम के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से वाहन के प्रावधान की आवश्यकता होती है।